


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| | साअधिकार प्रकाशित | <i>Published by Authority</i> |
| | आश्विन 12, शुक्रवार, शाके 1941-अक्टूबर 4, 2019 <i>Asvina 12, Friday, Saka 1941-October 4, 2019</i> | |

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 03, 2019

जी.एस.आर.20 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 7 का संशोधन.- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 7 में,-

(i) नियम 7 के विद्यमान उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (5) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(5) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार द्वारा अधिसूचित जनजाति उपयोजना (टी.एस.पी.) क्षेत्रों में रिक्तियों का आरक्षण, सरकार द्वारा अनुपालित जनजाति उपयोजना (टी.एस.पी.) कार्यक्रमों के अनुसार होगा।”

(ii) विद्यमान उप-नियम 7-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“7-घ संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:- सेवा में भर्ती के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, इस निमित्त समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों के अनुसार होगा। ”

(iii) विद्यमान उप-नियम 7-ड में विद्यमान अभिव्यक्ति “ एक प्रतिशत” के स्थान पर अभिव्यक्ति “5 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) विद्यमान उप-नियम 7-च के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 7-छ जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“7 (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी। ऐसे व्यक्ति भी, जिनका कुटुम्ब निम्नलिखित आस्तियों में से किसी भी आस्ति का स्वामी है या उन्हें रखता है, उक्त कुटुम्ब-आय को विचार में लाए बिना "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के रूप में पहचान किये जाने से अपवर्जित किये जायेंगे:-

- (i) पांच एकड़ और अधिक की कृषि भूमि;
- (ii) 1000 वर्ग फुट और अधिक का आवासीय फ्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और अधिक का आवासीय भू-खण्ड; या
- (iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और अधिक का आवासीय भू-खण्ड। "

3. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 में,-

- (i) विद्यमान उप खण्ड (घ) और (ङ) हटाये जायेंगे।
- (ii) नियम 8 के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
" परन्तु (ख) और (ग) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता का प्रमाणपत्र दे दिया हो।"

4. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 में,-

- (i) नियम 9 के अधिष्ठायी भाग में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अन्तिम तारीख को" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख से आगे आने वाले जनवरी माह के प्रथम दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) उप-नियम 9 के परन्तुक (i) में विद्यमान शब्द "और" के स्थान पर -विराम चिन्ह "," प्रतिस्थापित किया जायेगा और विद्यमान अभिव्यक्ति "अन्य पिछड़े वर्गों" के पश्चात् अभिव्यक्ति "और अति पिछड़े वर्गों" जोड़ी जायेगी।
- (iii) नियम 9 के विद्यमान परन्तुक (v) और परन्तुक (vi) हटाये जायेंगे।
- (iv) नियम 9 के विद्यमान परन्तुक (x) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"(x) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में ऐसी छुट अनुज्ञेय होगी जैसी समय-समय पर राज्य सरकार में लागू हो।"
- (v) नियम 9 के विद्यमान परन्तुक (xi) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक (xii) और (xiii) जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(xiii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

(xiii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे।”

5. नियम 11 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 में विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे ही दो” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे दो” प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 15 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय भर्ती प्राधिकारी या, यथास्थिति, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।”

7. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों नियम 19 में:-

(i) उप-नियम (i) का विद्यमान परन्तुक और विद्यमान अतिरिक्त परन्तुक हटाया जायेगा।

(ii) विद्यमान उप-नियम (i) के नीचे टिप्पण (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) अभ्यर्थी, जो अर्हित हो गया है, के नाम के सामने अभ्युक्तियां स्तंभ में प्रविष्टि की जायेगी।”

(iii) विद्यमान टिप्पण (2) में शब्द “किया जायेगा” के पश्चात् विराम चिन्ह “। ” अंतःस्थापित किया जायेगा।

8. नये नियम 19क का अंतस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 19क जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“19 क. आरक्षित सूची:- अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के पचास प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार आरक्षित सूची भी भर्ती प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। अध्यपेक्षा किये जाने पर भर्ती प्राधिकारी, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल चयन सूची भर्ती प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, एक वर्ष के भीतर-भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

9. लिपिक ग्रेड-II के लिए अनुसूची-I के भाग-I में संशोधन.-

(i) अनुसूची-I के भाग-I के विद्यमान टिप्पण (ii) में अभिव्यक्ति “50 प्रतिशत” के स्थान पर “45 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) अनुसूची-I के भाग-I के विद्यमान टिप्पण (ii) में अभिव्यक्ति “45 प्रतिशत” के स्थान पर “40 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) अनुसूची-I के भाग-I के विद्यमान टिप्पण (ii) में अभिव्यक्ति “विशेषयोग्यजन और अजा/अजजा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) अनुसूची-I के भाग-I के विद्यमान टिप्पण (ii) में अभिव्यक्ति “नियुक्ति प्राधिकारी” के स्थान पर अभिव्यक्ति “भर्ती प्राधिकारी” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) अनुसूची-I के भाग-I के विद्यमान टिप्पण (ii) के पश्चात् नया टिप्पण (iii) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(iii) कोई अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा में, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन व्यक्तियों के मामले में कम से कम 40 प्रतिशत और समस्त अन्य

प्रवर्गों के मामले में 45 प्रतिशत अंकों के साथ कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, चयनित नहीं किया जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं तो उनके नाम सामान्य उपयुक्तता के आधार पर व्यवस्थित किये जायेंगे।

[सं. एफ. 3(33)डीओपी/ए-II/85 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 03, 2019

G.S.R. .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan, in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Rule 7.**- In rule 7 of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) After the existing sub rule (4) of rule 7, the following new sub rule (5), shall be added, namely:-

“(5) Notwithstanding anything contained in this rule, reservation of vacancies for Tribal Sub Plan areas notified by the Government shall be as per the Tribal Sub Plan Programme followed by the Government.”

(ii) The existing rule 7-D, shall be substituted by the following, namely:-

“7-D. **Reservation of vacancies for Persons with benchmark disabilities.**- Reservation of vacancies for persons with benchmark disabilities in the recruitment to the service shall be in accordance with the Rules of the Government issued from time to time in this behalf.”

(iii) In the existing rule 7-E, for the existing expression “1%”, the expression “5%” shall be substituted.

(iv) After the existing rule 7-F, the following rule 7-G, shall be added, namely:-

“7-G.**Reservation for Economically Weaker Sections**-Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule ‘Economically Weaker Sections’ shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the persons who seek benefit of reservation, his/her parents and siblings below the

age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as, 'Economically Weaker Sections', irrespective of the family income:-

- (i) 5 acres of Agriculture Land and above;
- (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- (iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities; or
- (iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities."

3. **Amendment of Rule 8.-** In rule 8 of the said rules,-

- (i) the existing sub clause (d) & (e) shall be deleted.
- (ii) the existing proviso to rule 8, shall be substituted by the following, namely:-
"Provided that a candidate belonging to categories (b) & (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India."

4. **Amendment of Rule 9.-** In rule 9 of the said rules , -

- (i) In substantive part of rule 9, the existing expression "last date fixed for submission of application" shall be substituted by the expression "first day of January next following the last date fixed for receipt of application."
- (ii) In proviso (i) to rule 9, the existing word "and" shall be substituted by the punctuation ",", and the existing expression "and More Backward Classes" shall be added after expression "Other Backward Classes."
- (iii) the existing proviso (v) and proviso (vi) to rule 9, shall be deleted.
- (iv) the existing proviso (x) to rule 9, shall be substituted, namely:-
" (x) the age relaxation for persons with disabilities will be admissible as applicable in the State Government from time to time."
- (v) After the existing proviso (xi) to rule 9, the following provisos (xii) and (xiii) shall be added, namely:-
" (xii) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
(xiii) the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit and shall be allowed up to two chances."

5. **Amendment of Rule 11.-** In the existing rule 11 of the said rules, the word "each" in between the words "two" and "certificates" shall be substituted by the word "such".

6. **Amendment of Rule 15.-** In the existing rule 15 of the said rules, following proviso shall be added, namely:

"Provided that while selecting candidates for the posts, so advertised, the Recruiting Authority, as the case may be, may, if intimation of additional requirement, not exceeding 50% of the advertised

vacancies is received by it for selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.”

7. **Amendment of Rule 19.-** In rule 19 of the said rules:-
 - (i) the existing proviso and existing further proviso to sub rule (i) shall be deleted.
 - (ii) the Note (1) below the existing sub rule (i) shall be substituted by the following, namely:
 - “(1) An entry shall be made in the remarks column against the name of a candidate who has qualified.”
 - (iii) In the existing Note (2) after the words “High Court” punctuation mark “.” shall be inserted.
8. **Insertion of new Rule 19A.-** After the existing rule 19 of the said rules, the following new rule 19A, shall be added, namely:
 - “19A. Reserve List:- A category wise reserve list of suitable candidates to the extent of fifty percent of the finally intimated vacancies shall also be prepared by the Recruiting Authority. The Recruiting Authority on requisition shall send the names of such candidates in order of merit to the Appointing Authority concerned, within a year from the date on which original select list was forwarded by the Recruiting Authority.”
9. **Amendment in Part –I of Schedule-I for Clerk Grade-II .-**
 - (i) In existing Note (ii) of Part-I of Schedule-I, the expression “50%” shall be substituted by the expression “45%”.
 - (ii) In existing Note (ii) of Part-I of Schedule-I, the expression “45%” shall be substituted by the expression “40%”.
 - (iii) In existing Note (ii) of Part-I of Schedule-I, the expression “Specially Abled Persons and SC/ST”, shall be substituted by the expression “Scheduled Caste / Scheduled Tribes & Specially Abled Persons”.
 - (iv) In existing Note (ii) of Part-I of Schedule-I, the expression “Appointing Authority”, shall be substituted by the expression “Recruiting Authority”.
 - (v) After existing Note (ii) of Part-I of Schedule-I, new note as Note (iii), shall be added, namely:-
 - “(iii) No candidate who failed to secure 50% in the aggregate with at least 40% marks in case of Scheduled Caste / Scheduled Tribes & Specially Abled persons and 45% marks in case of all other categories, in each test, at the competitive examination shall be selected. If two or more of such candidates obtain equal marks in the aggregate, their names shall be arranged on the basis of general suitability.”

[No. F.3(33)DOP/A-II/85 Pt.]

By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,

DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।